



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]  
No. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 285(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 229”

अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 को, जहां तक इसका संबंध झारखंड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से है, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनःपरिभाषित किया जाता है:—

झारखंड

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला

5. लातेहार जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामताड़ा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

**स्पष्टीकरण** :—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त क्षेत्र वही हैं, चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारा जाए, जो सं. आ. 109 [अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977], तारीख 31 दिसम्बर, 1977 द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य के भाग के रूप में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित किए गए हैं।

3. पूर्ववर्ती पैरा में प्रादेशिक खंड, उसे चाहे किसी नाम से उपदर्शित किया गया हो, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारंभ पर उस नाम से विद्यमान प्रादेशिक खंड के प्रतिनिर्देश है।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,  
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(8)/2006-वि. 1]

के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(Legislative Department)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2007

**G.S.R. 285(E).**— The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 229”

**The Scheduled Areas (State of Jharkhand)  
Order, 2007**

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003 in so far as it relates to the areas now comprised in the State of Jharkhand and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely :

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Jharkhand) Order, 2007.
- (2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Jharkhand :—

**JHARKHAND**

1. Ranchi District
2. Lohardaga District
3. Gumla District
4. Simdega District

5. Latehar District
6. East-Singhbhum District
7. West-Singhbhum District
8. Saraikela-Kharsawan District
9. Sahebganj District
10. Dumka District
11. Pakur District
12. Jamtara District
13. Palamu District— Rabda and Bakoria Panchayats of Satharwa Block
14. Garhwa District—Bhandaria Block
15. Godda District—Sunderpahari and Boarijor Blocks.

*Explanation.*—For the removal of doubts, it is hereby declared that the said areas are the same, by whatever name called, as were notified as Scheduled Areas as part of the erstwhile State of Bihar *vide* C.O. 109 [the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977], dated the 31st December, 1977.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

A. P. J. ABDUL KALAM,  
President.

[F. No. 19(8)/2006-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.